

# भाजपा को 52 प्रतिशत वोटों के साथ 148 सीटों पर बम्पर जीत की भविष्यवाणी

## इंडिया टी.वी. के एक सर्वे में यह भविष्यवाणी की गई है

जयपुर, 30 जुलाई (का.प्र.)। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदना के विधानसभा क्षेत्र हिंडोली में हुई एक भीड़ भरी सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंच पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी सहित आधा दर्जन मंत्री और कांग्रेस नेता दगदग नजर आ रहे थे। मौका था 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के शिलान्यास का। यह खुशी ज्यादा ठहरती, इससे पहले ही एक नेशनल न्यूज चैनल ने चुनावी सर्वे दिखाया और उस सर्वे में राजस्थान में कांग्रेस की हालत पिछली बार के मुकाबले बेहद कमजोर बताते हुए सीधे सीधे भाजपा की बंपर जीत बतायी।

हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी 15 महीने का समय बाकी है और उस वक्त की परिस्थितियां ही चुनावी हार-जीत तय करेंगी। फिर भी कांग्रेस के आंतरिक हालातों के कारण वर्तमान में जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, उससे खुद कांग्रेस का आम कार्यकर्ता निराश नजर आता है। वैसे सरकार के नजदीकी

■ सर्वे के अनुसार, कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोटों के साथ 42 सीटें मिलेंगी तथा 10 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी।

■ हालांकि इसी सर्वे में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत को प्रथम, तो पायलट को चौथे नम्बर पर बताया गया है, और वसुंधरा राजे और गजेन्द्र सिंह को क्रमशः दूसरे और तीसरे नम्बर पर बताया गया है, सर्वे की यह ही बात लोगों के गले नहीं उतर रही है।

■ वैसे भी राजस्थान के चुनावों में 15 महीने का समय बाकी है, जो परिस्थितियों को बदल सकता है।

लोग हमेशा की तरह भुलावे में बात करते हुए सरकार रिपोर्ट होने की बात करते हैं। बात की जाए चुनावी सर्वे की तो राजस्थान में आम लोगों में चर्चाओं का केंद्र भी यही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार का रिपोर्ट होना संभव नजर नहीं आता। लोगों के इसी टेस्ट के अनुरूप इंडिया न्यूज के चुनावी सर्वे ने राजस्थान को लेकर कहा है कि आज की स्थिति में चुनाव होते हैं, तो भाजपा को 52 प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं।

वहीं भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोट मिलेंगे। यानी कि कांग्रेस और भाजपा में हार जीत का फासला 21 प्रतिशत से ज्यादा मतों का रहने वाला है। वहीं चैनल ने राजस्थान में आज की स्थिति में चुनाव होने पर भाजपा के खाते में बंपर जीत के साथ में 148 सीटें दी है, तो कांग्रेस के खाते में आज की स्थिति में 42 सीटें चैनल के अनुरूप आ सकती है। बाकी अन्य दलों के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई देती है, उनके खाते में 17 प्रतिशत वोट

आ सकते हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 99 और भाजपा ने 73 सीटें जीती थी।

वर्तमान परिस्थितियों में इस वोट प्रतिशत और सीटों के आकलन को लेकर बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस टीवी चैनल के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर भी जिन नामों का जिक्र है, उन्हें मिले मत प्रतिशत से लोग सहमत नजर नहीं आते दिख रहे हैं। सर्वे की मजेदार बात यह है कि जहां कांग्रेस को यह चैनल सिर्फ 48 सीटें और 31 प्रतिशत वोट दे रहा है, वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 27 प्रतिशत वोटों के साथ जनता की पसंद में सबसे आगे बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 22 प्रतिशत वोटों की पसंद के रूप में नंबर दो पर माना गया है। जो अन्य नाम मुख्यमंत्री के रूप में इस टीवी चैनल के सर्वे में आए हैं, वे हैं भाजपा के गजेन्द्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के सचिन पायलट। इनमें से गजेन्द्र सिंह शेखावत की लोकप्रियता 19 प्रतिशत लोगों में बताई गई है, तो सचिन पायलट

मुख्यमंत्री के रूप में 11 प्रतिशत लोगों की पसंद बताए गए हैं। यह बात शायद ही राजस्थान में राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों के समझ में आए कि गजेन्द्र सिंह शेखावत सचिन पायलट से ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गए हैं। यह बात इसलिए भी कही जा रही है कि कुछ दिन पहले ही देशभर में लोकप्रियता के मामले में कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के अलावा अन्य नेताओं की लोकप्रियता का एक सर्वे सामने आया था। उस सर्वे में गांधी परिवार के अलावा पार्टी में अन्य लोकप्रिय नेताओं में मनमोहन सिंह के बाद सचिन पायलट सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में शुमार हुए थे।

वैसे भी इस सर्वे के सामने आने के बाद लोगों का मूड भले ही भाजपा की ओर नजर आ रहा हो, लेकिन यदि आने वाले दिनों में कांग्रेस की आंतरिक परिस्थितियों में बदलाव आता है, तो यह स्थिति बदलने में भी समय नहीं लगेगा। ऐसे में सर्वे को फिलहाल जनता का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है।

# नकली नोट मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेगा

## राज्य के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने इस संबंध में आदेश जारी किए

बीकानेर, 30 जुलाई (का.प्र.)। नकली नोट मामले में अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) जांच करेगा। पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने उक्त आदेश दिए हैं। ऐसे में बीकानेर पुलिस अब तक की जांच रिपोर्ट एस.ओ.जी. को सौंप देगी। इस मामले में अब तक सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सभी को एस.ओ.जी. के हवाले किया जा रहा है। जांच पड़ताल में 43 युवकों के नाम सामने आये हैं, जिनका डोज़ियर बनाकर एस.ओ.जी. को सौंपा जायेगा।

जिले में नकली नोट छापने का कारखाना सिर्फ बुंदान एन्क्लेव में नहीं बल्कि दो से तीन जगहों पर चल रहा था। बीकानेर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब नौखा के सुरपुरा में मास्टर माईड चम्पालाल के घर से पुलिस को प्रिंटर के साथ 14.56 लाख रुपये के नकली नोट मिले। आशंका जताई जा रही है कि, करोड़ों रुपये के नोट सुरपुरा से छापकर भी बाजार में चलाये गए हैं। मास्टर माईड सुरपुरा के चम्पालाल के घर पर आईजी ऑफिस की विशेष

■ अब तक सात आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तथा 43 अन्य युवकों के नाम भी सामने आए हैं। बीकानेर पुलिस इनका डोज़ियर बनाकर एस.ओ.जी. को सौंपेगी।

टीम द्वारा की गई छानबीन में नकली नोट एवं प्रिंटर मिला था। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ से 4 लाख 43 हजार रुपये के असली नोट भी बरामद किए। ये रुपये चम्पालाल ने जाली नोट के बदले लिए थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि ये रुपये किससे और कितने जाली नोट के बदले लिए गए थे।

गिराह के बुंदान एन्क्लेव में स्थित मकान से पुलिस को दो करोड़ 74 लाख रुपये के नकली नोट व प्रिंटर सहित काफी महत्वपूर्ण सामान मिला था। इसके बाद रिकवॉर जाखड़ से भी 14 लाख

86 हजार के नकली नोट, एक प्रिंटर, दो कागज के रिम बरामद हुए हैं। यह बरामदगी जाखड़ के वैष्णोधाम के पास स्थित कमरे से हुई है, जो उसने किराये पर ले रखा था।

इससे पूर्व टीम ने दीपक जीनगर के लूणकनसर स्थित घर से 6 लाख 30 हजार रुपये और एक पेपर कटर बरामद किया। इस दौरान दो लाख 56 हजार रुपये के नोट पूरी तरह प्रिंट होकर रखे मिले। इसमें पांच सौ व दो हजार रुपये के जाली नोट हैं। बाकी रकम अधूरी प्रिंट हो रखी थी। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जांच शुरू कर दी है। बैंक के अधिकारियों ने गिरफ्तार युवकों से भी पूछताछ शुरू की है। नकली नोटों का परीक्षण भी किया जा रहा है। रिजर्व बैंक यह पता लगाने में जुटा है कि, नकली नोट छापने के बाद कहाँ-कहाँ बाजार में उतारे गए। नोटों की सीरीज सहित कई तकनीकी मामलों में छानबीन हो रही है।

### इन्कम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करोड़ आई.टी.आर. फाइल हुई थी और सितम्बर 2021 में 5.70 करोड़ आई.टी.आर. फाइल हुई थी। 128 जुलाई को 30 लाख आई.टी.आर. जमा की गई जबकि तब तीन दिन शेष थे। उम्मीद है फाइल की गई आई.टी.आर. की संख्या 5000 से अधिक हो जाएगी पूर्व में भी अंतिम दो दिनों में आई.टी.आर. का संस्था में भारी उछाल आते देखा गया है। इसका अर्थ है कि आई.टी.आर. की संख्या 4.4 करोड़ से 5.55 करोड़ के बीच ह सकती है, इस स्थिति के अंतिम तिथि बढ़ाने की संभावना कम है।

### 'मेघालय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा ने इस कदम को राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। इस सरकार में भाजपा की भी आंशिक भागीदारी है।

# शराब नीति बदलने को मजबूर हुई दिल्ली सरकार

## दिल्ली में एक अगस्त से शराब की निजी दुकानें बंद हो जायेंगी, सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब बिकेगी

नई दिल्ली, 30 जुलाई। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने का फैसला किया है और 1 अगस्त से केवल सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से ही शराब बेचने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और अब शराब की बिक्री केवल सरकारी दुकानों से करने का निर्देश दिया गया है। सिंसोदिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम

■ उप मुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया ने कहा कि, भाजपा सी.बी.आई. और इ.डी. के माध्यम से लाइसेंसधारियों और आबकारी अधिकारियों को लगातार धमकाती आ रही है, भाजपा के कारण ही टैंडर प्रक्रिया के बावजूद 850 शराब की दुकानों में से केवल 468 ही खुल सकी थीं।

■ सिंसोदिया ने कहा कि, गुजरात की तरह ही भाजपा दिल्ली में भी अवैध शराब की बिक्री होते रहने देना चाहती है।

से बेची जाए और कोई अराजकता न हो। सरकार के इस फैसले के चलते दिल्ली में चल रही 468 निजी शराब की दुकानें 1 अगस्त से उनके लाइसेंस की अवधि खत्म होने के चलते बंद हो जाएंगी। नई आबकारी नीति के तहत की अवधि को 30 अप्रैल के बाद दो बार

दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त होगी। सिंसोदिया ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी आबकारी नीति में कई सरकारी शराब की दुकानें थीं और ऐसी दुकानों में भारी भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन नई

आबकारी नीति के साथ इसे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में खुली निविदाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से लाइसेंस जारी किए गए हैं। सिंसोदिया ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में सरकार को 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जबकि नई आबकारी नीति से सरकार को पूरे वर्ष में 9,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना तय था।

भाजपा पर सी.बी.आई. और इ.डी. के माध्यम से लाइसेंसधारियों और आबकारी अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए सिंसोदिया ने दावा किया कि 850 शराब की दुकानों में से केवल 468 ही खुल सकी, क्योंकि कई को दुकान मालिकों ने भाजपा की धमकी के बाद बंद कर दिया था।

### दिल्ली में प्र.मंत्री व राष्ट्रपति आवास का घेराव होगा

नई दिल्ली, 30 जुलाई। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी अपने बड़े विरोध के तहत संसद से राष्ट्रपति भवन और "प्रधानमंत्री हाउस घेराव" तक मार्च निकालने का ऐलान कर चुकी है।

देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पी.एम. हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस मार्च में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के

■ कांग्रेस महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।

शामिल होने की संभावना है। संसद के दोनों सदन में इस सप्ताह मूल्य वृद्धि मुद्दे पर कई व्यवधान देखे गए। लोकसभा में सोमवार को महंगाई पर बहस होने की संभावना है, उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर बहस हो सकती है।

गौरतलब है कि, विपक्ष 18 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदन में बढ़ती कीमतों और जी.एस.टी. का मुद्दा उठा रहा है।

### महंगाई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक पत्र भेजकर क्षमा याचना की है। स्पीकर ओम बिड़ला को चौधरी द्वारा किए गए एक विरोध पर निर्णय करना है।

चौधरी ने राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि केन्द्रीय महिला एवं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति मुमू के नाम से पूर्व श्रीमती शब्द नहीं लगाया था। उन्होंने यह मांग भी की थी उनकी ज़बान फिसलने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम घसीटने को लेकर ईरानी और भाजपा के सदस्यों की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए।

### झारखण्ड के तीन विधायकों की कार से करोड़ों रु. कैश बरामद

हावड़ा, 30 जुलाई। झारखण्ड के कांग्रेस विधायकों को गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, बड़ी मात्रा में नोट होने के कारण की गिनती नहीं हो पाई है, वह कैश करोड़ों में होने की पूरी संभावना है।

पुलिस द्वारा यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के हावड़ा में की गई है। बताया जा रहा है कि तीन विधायकों को गाड़ी से यह कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने इनपुट के बाद चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी थी। बताया जा रहा है कि कैश की गिनती के लिए कार्टींग मशीन मंगाई गई है।

एस.पी. स्वाति भंगालिया ने बताया कि हमने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा है।

### 'अगर सभी राजस्थानी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के राज्यपाल ने कहा था कि "यदि गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, खासतौर मुम्बई और ठाणे से तो, वहां घन नाम की चीज नहीं रहेगी।" उन्होंने आगे कहा था कि तब मुम्बई देश की वित्तीय राजधानी नहीं रह जाएगी।

अक्सर का लाभ उठाते हुए अल्वा ने अपने प्रहार में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ को भी निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि "महाराष्ट्र के राज्यपाल की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं, किन्तु अप्रत्याशित नहीं हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल एवं उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से जो मैसेज प्राप्त किया है, वह है: विवाद, भ्रूखतापूर्ण टिप्पणियां और संबिधानेतर व्यक्तित्व की भांति कार्य करना और उस व्यवहार का पुरस्कृत किया जाना!"

अल्वा उप राष्ट्रपति चुनाव में

धनखड़ के विरुद्ध प्रत्याशी हैं। धनखड़ को भाजपा नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) ने अपना प्रत्याशी बनाया है।

धनखड़ और बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस सरकार की प्रायः प्रशासन से लकर राजनीतिक मुद्दों पर झड़पें हुईं, जिसमें बनर्जी की पार्टी ने राज्यपाल पर अक्सर आरोप लगाया कि वह राज्य के मामले में दखलदर्जी कर रहे हैं जिसमें नई दिल्ली की रिमोट कंट्रोल भूमिका है।

अन्ततः धनखड़-बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा सरमा के बीच एक मीटिंग हुई जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की कि वह 6 अगस्त को होने जा रहे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से अग्रपंथित रहेगी।

धनखड़ भारत के उप राष्ट्रपति बनने के बाद बंगाल से दिल्ली पहुंच जाएंगे और बनर्जी के एि यह एक बड़ी जीत होगी।

# 'बाद में मत कहना, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रद्द करवा देगा, फिर भी हाल ही के दिनों में आंतरिक चिंताएं और तीव्र हो गई हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन पेलेोसी का प्रस्तावित दौरा रोकने की चुपचाप कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट एक स्थिति के बारे में बताती है जिसमें चीन पेलेोसी के अमेरिकी सैन्य विमान को "एस्कोट" करने के लिए एक एयरक्राफ्ट भेज सकता है ताकि यदि पेलेोसी ताइवान का दौरा करना चाहे तो उन्हें वहाँ लैंड करने से रोका जा सके और एक अमेरिकी ने कहा कि यह स्थिति चिंता का एक न्यायिक विषय है। चीन के विश्लेषकों ने बताया कि चीन की कड़ी चेतावनियों का अर्थ है कि यदि पेलेोसी इस देश का दौरा करती है तो उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) सभी संभावित चुनौतियों से निबटने के लिए पूर्णतया तैयार है और उन्होंने पी.एल.ए. की रॉकेट फोर्स को सलाह दी कि वह पेलेोसी की यात्रा में

शामिल किसी भी संभावित अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य बड़े सैन्य जहाजों को निशाना बनाने के लिए नई मिसाइल को ड्रिल करना शुरू कर दे।

चीन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रवक्ता तान केपी ने कहा है कि यदि अमेरिका के तीसरे नम्बर की नेता पेलेोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो यह "वन-चाइना" सिद्धांत और चीन-अमेरिका के तीन संयुक्त शासकीय परिपत्रों का गंभीर उल्लंघन होगा और इससे चीन-अमेरिका संबंधों के राजनीतिक आधार सहित चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता गंभीर रूप से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को जबरदस्त क्षति पहुंचेगी और ताइवान जलदमरुमध्य में तनाव बढ़ जाएगा।

तान ने कहा कि चीन अमेरिका से मांग करता है कि वह ताइवान के अलगाव का समर्थन नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे और

पेलेोसी के ताइवान दौरा का प्रबंध ना करे। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यदि अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहता है तो चीन की सेना किसी भी सूत्र में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप तथा ताइवान की स्वतंत्रता के प्रयासों को दूर करने के कड़े उपाय करेंगी और राष्ट्रीय संप्रभुता व क्षेत्रीय अखण्डता की मजबूती से रक्षा करेगी। बताया जाता है कि इस्टीमेटेड ऑफ अमेरिकन स्टडीज ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के उप निदेशक एवं सीनियर फैलो युआन झोंग ने चीन की सरकार को सलाह दी है कि यदि पेलेोसी ताइवान की यात्रा करती है तो उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं। उन्हें चीन, हॉंगकॉंग और मकाओ में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाए और उनसे सम्बद्ध संस्थानों को भी चीन के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए।